

रेलवे मंत्री (श्री बे० मु० पुनाचा) :

(क) चूँकि निर्धारित जलमार्ग नहीं था इसलिए मक्सो-शाजापुर खण्ड पर किलोमीटर 4 और 5 के बीच शुरू में कोई पुल नहीं बनाया गया था। मिट्टी का काम पूरा हो जाने के बाद ही पुल की ज़रूरत का पता चला। इसलिए इस क्षेत्र में रुके हुए पानी को निकालने के लिए 1-15 फुट स्पैन की प्रतिबलित सीमेंट-कांक्रिट की सिल्ली वाली एक पुलिया बाद में बनायी गयी। पुल की अनुमानित लागत लगभग 30,000 रुपये थी न कि 90,000 रुपये।

(ख) छावनी स्टेशन (कैट स्टेशन नहीं) के समीप समपार सं० 6 के पहुंच मार्ग पर 1-12 फुट प्रतिबलित सीमेंट-कांक्रिट की सिल्ली वाली एक पुलिया बनाकर आवश्यक शार-पार नाली की पहले ही व्यवस्था कर दी गयी है। इसलिए वर्षा के कारण पुश्ते के किसी भाग के बह जाने की कोई समावना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मोर के पंखों का निर्यात

7142. श्री श्रीकार सिंह :

श्री हुकम चन्व कछवाय :

क्या वाणिज्य मंत्री 31 मार्च, 1967 के अंतरांकित प्रश्न संख्या 335 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि मोर के पंखों को, जिन से काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है, एकत्र करने के लिये राज्य सरकारों ने कोई व्यवस्था नहीं की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को इस बारे में हिदायतें जारी करने का है ताकि उनका निर्यात पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया जा सके; और

(ग) क्या सरकार का विचार पंख एकत्र करने वालों से भी निर्यात के लिये पंख खरीदने की कोई व्यवस्था करने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) से (ग). मोर के पंख निजी व्यापारियों द्वारा एकत्र और निर्यात किये जा रहे हैं। राज्य सरकारों से निर्यात बढ़ाने के लिये अनुरोध करने का सरकार का कोई विचार नहीं है और पंख एकत्र करने वालों से मोर के पंख खरीदने की भी सरकार का विचार नहीं है।

अवांछित तरीकों से पंख एकत्र करने को रोकने के लिये सीमित वार्षिक कोटे के अंदर अंदर निर्यात को अनुमति दी जाती है।

Exports to Neighbouring Countries

7143. **Shri Ram Krishan Gupta:** Will the Minister of Commerce be pleased to state the steps taken to sustain exports to neighbouring countries like Ceylon, Burma and Nepal with a view to evolve effective measures to meet the Chinese challenge in these natural markets for the Indian exports?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): A number of measures have been taken by the Government of India to expand and diversifying our exports to the neighbouring countries. Trade Agreements/Arrangements have been concluded with Afghanistan, Ceylon, Indonesia, Iran, Japan, and Nepal. We are also negotiating Trade Agreements with the Governments of Burma, Malayasia and Thailand. With a view to assist the friendly countries in purchasing their essential requirements in India, loans and credits have been granted to countries like Ceylon, Indonesia and Nepal. Deferred-payment facilities are also being granted on merits to facilitate export of items like capital goods and engineering items. Our Trade Representatives in these countries keep a close watch on the economic trends, and they advise the concerned Export Promotion

Councils. About the trading opportunities as and when these arise in their respective countries. Trade Delegations are sponsored from time to time to acquaint importers in other countries with the progress made by Indian in the industrial field, and the wide range of products now available for export to these countries. In order to popularise Indian goods, show rooms and trade centres have been set up in neighbouring countries such as Afghanistan and Thailand. India also participates in important trade fairs in these countries and exclusively Indian exhibitions are also organized to demonstrate the quality of our products. Necessary assistance is given to encourage visit of Indian business men to these countries besides the trade teams sponsored by Export Promotion Councils, to enable them to establish closer contacts with India's trading partners and to ascertain developments relating to other competing countries.

गाजियाबाद होकर हापुड़ के लिये एक पार्सल एक्सप्रेस का चलाया जाना

7144. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन में व्यापारियों ने अपनी उन कठिनाइयों के बारे में लिखा है, जिनका वे हथ करघे के कपड़े को उत्तरी रेलवे के पिलखुवा और हापुड़ स्टेशनों से अन्य राज्यों को भेजने में अनुभव करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने अपने अभ्यावेदन में इस बात की शिकायत की है कि उनका माल गन्तव्य स्थानों पर देर से पहुंचता है और अपना माल लादने में उन्हें बड़ी असुविधा होता है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है और यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या ऐसे मुझाव प्राप्त हुए हैं कि पार्सल एक्सप्रेस को गाजियाबाद से हापुड़ और बुलन्दशहर होकर चलाया जाये और यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री वे० मु० पुनाचा) :

(क) और (ख). जी हां ।

(ग) अभ्यावेदन में दी गयी बातों की जांच की गयी है । पिछली व्यस्त अवधि में स्थिति को सम्हालने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये थे और आने वाली व्यस्त अवधि में भी ये उपाय बरतने का विचार है :—

(1) हापुड़ और उस खण्ड के दूसरे स्टेशनों से होने वाले हैंडलूम के यातायात की निकासी के लिए एक बोगी पार्सल यान या सवारी गाड़ी के साथ चलने के उपयुक्त दो माल डिब्बे हर रोज मेरठ से खुरजा तक नं० 4 के० एम० सवारी गाड़ी के साथ लगाये जाते हैं । खुरजा में इन्हें मुगलसराय के लिए 72 डाउन पार्सल एक्सप्रेस के साथ लगा दिया जाता है ।

(2) पिलखुवा और दूसरे स्टेशनों से होने वाले हैंडलूम के यातायात की निकासी के लिए एक बोगी पार्सल यान या सवारी गाड़ी के साथ चलने के उपयुक्त दो माल डिब्बे हर रोज दिल्ली से मुरादाबाद तक नं० 2 एम डी० सवारी गाड़ी में लगाये जाते हैं । मुरादाबाद से मुगलसराय के लिए इन्हें 74 डाउन पार्सल एक्सप्रेस के साथ लगा दिया जाता है ।

इनके अलावा, नीचे लिखे उपाय भी किये जा रहे हैं :

(1) हैंडलूम परेशनों के सदान की सुविधा के लिए पिलखुवा में एक माइडिंग का निर्माण किया जा रहा है ।